SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, in this scheme of affordable housing for poor, in the reply also, it is said, 'this is for key cities.' I would like to know which cities are included in it. What are the names of those cities? The is part(a) of my question. Sir, as a part of this question, if the Government is serious about this scheme, if the Government wants to protect those lands which are vacant today, will the Government introduce reservation in the development plan of the concerned cities? I want to know whether it can say that these plots are reserved for housing for poor. I want to know whether this type of reservation can be introduced.

KUMARI SELJA: Sir, the National Urban Housing and Habitat Policy as well as the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission has clearly stated that 20-25 per cent of the land must be reserved for the poor and, at least, 10-15 per cent of the land must be reserved for the urban poor, or 20-25 per cent of the developed land or dwelling units must be reserved for the urban poor. The Government has been taking this up with the State Governments from time to time. But, Sir, the hon. Member would appreciate that ours is a federal structure and the Central Government can only try to persuade and impress upon the respective State Governments to take up these issues, which affect them as much as the Central Government and they are as concerned about the urban poor as the Central Government. There are various schemes like the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission which are worked out in partnership with the State Governments and local bodies, and to make it a success, the State Governments have assured the Central Government, by taking up the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, that they will take care of these aspects.

SHRI PENUMALLI MADHU: Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister to Hyderabad where land that was procured for housing for the weaker sections of society was handed over to a Singapore company. While the hon. Minister is assuring us that affordable housing would be made available for the poor, land procured for the poor is being given away to the Singapore company. Will the Minister assure us that land will be made available for housing? I am talking about Hyderabad.

KUMARI SELJA: Sir, as I said in the beginning, land is the property of the State Government. They have various projects which are upcoming, which they have, sanctioned. I am not aware of each and every project in each and every State, but this is an issue which concerns the State Government.

भ्रष्टाचार के संबंध में वैश्विक सर्वेक्षण

†*85. **श्री जनेश्वर मिश्र** :††

श्री बृजभूषण तिवारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान वैश्विक सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिसमें देश की उच्च नौकरशाही को भ्रष्टतम करार दिया गया है;

---

††सभा में यह प्रश्न श्री जनेश्वर मिश्र द्वारा पूछा गया।

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की भी जानकारी है कि देश की जनता की दयनीय हालत का एक मूल कारण यह भ्रष्ट नौकरशाही व्यवस्था है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) इस बारे में एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार को ऐसे किसी वैश्विक सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है जिसने भारतीय नौकरशाही को भ्रष्टतम नौकरशाही करार दिया है। तथापि, हांगकांग की एक राजनैतिक और आर्थिक जोखिम परामर्शदायी संस्था ने 12 उत्तरी और दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बिजनेस सर्वेक्षण में भारत की नौकरशाही को सबसे कम कार्यकुशल पाया है।

वर्ष 2009 में ट्रान्सपैरेन्सी इन्टरनेशनल ने 'वैश्विक भ्रष्टाचार मापी, 2009' नामक एक सर्वेक्षण प्रकाशित किया है। यह सर्वेक्षण विश्वभर में भ्रष्टाचार पर सार्वजनिक राय और घूसखोरी के अनुभवों पर आधारित है। इस राय आधारित सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष यह है कि राजनैतिक दलों और सिविल सेवा को सामान्यतः विश्वभर में सबसे अधिक भ्रष्ट क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भ्रष्टाचार से निबटने में सरकार की कारगरता को बोध, भारत सहित 12 देशों में बढ़ा है। रिपोर्ट द्वारा दर्शाई गई समग्र तस्वीर से यह अभिप्राय नहीं है कि देश की उच्च नौकरशाही को सबसे अधिक भ्रष्ट करार दिया गया है अथवा यह देश की आम जनता की दुर्दशा का मुख्य कारण है।

(ग) सरकार 'भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं' की अपनी नीति को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध है और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाकर यह जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। भ्रष्टाचार से निबटने और सरकार के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:'

(i) भंडाफोड़ करने वालों से संबंधित (व्हिसल ब्लोअर्स) संकल्प, 2004 का जारी किया जाना;

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;

(iii) सतर्कता पर, वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से मंत्रालय/विभाग की निवारक उपाय के रूप में पूर्व-सक्रिय भागीदारी;

(iv) निविदा और संविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा व्यापक अनुदेश जारी किया जाना;

(v) सरकार की प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता अंगीकार किए जाने के बारे में संगठनों को कहते हुए, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी किया जाना; केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 16 जून, 2009 को, राज्य सरकार को अपनी बड़ी-बड़ी खरीद में सत्यनिष्ठा समझौता अंगीकार किए जाने की सलाह देते हुए इसी तरह के अनुदेश जारी किए गए हैं;

(vi) भारत उन देशों में से एक देश है जिसने भ्रष्टचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(vii) ई-शासन शुरु करना और प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरलीकरण करना;

(viii) नागरिक चार्टरों का जारी करना।

Global survey on corruption

†*85. SHRI JANESHWAR MISHRA: ††

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the global survey wherein the top bureaucracy of the country has been rated as most corrupt;

(b) whether Government is also aware of the fact that this corrupt bureaucratic system is one of the root causes of the plight of the masses of the country; and

(c) if so, the measures that are being taken by Government to bring in reforms and transparency in the system together with details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): (a) to (c) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) and (b) Government is not aware of any Global Survey which has ranked Indian Bureaucracy as the most corrupt. However, a Hong-Kong based Political and Economic Risk Consultancy has ranked India's bureaucracy as the least efficient in a business survey of 12 North and South Asian Economies.

In 2009, Transparency International has published a survey titled "Global Corruption Barometer 2009". The Survey is based on public opinion on Corruption as well as experiences of bribery around the world. One of the main findings of the opinion survey is that political parties and the civil service are perceived on average to be one of the most corrupt sectors around the world. The report also notes that the perception of Government effectiveness in relation to addressing Corruption has increased in 12 countries including India. The overall picture presented by the report does not imply that the top bureaucracy of the country has been rated as most corrupt, or is a root cause of the plight of the masses of the country.

(c) Government is fully committed to implement its policy of "Zero Tolerance against Corruption" and is moving progressively to eradicate corruption from all spheres of life by improving transparency and accountability. Several steps have been taken to combat corruption and to improve the functioning of Government. These include-

i) Issue of Whistle Blowers Resolution, 2004;

ii) Enactment of Right to Information Act, 2005;

iii) The pro-active involvement of Ministry/Department through Annual Action Plan on Vigilance as a preventive measure;

iv) Issue of comprehensive instructions on transparency in tendering and contracting process by the CVC;

---

† Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Janeshwar Mishra.

v) Issue of instructions by the CVC asking the organizations to adopt integrity pact in major Government procurement activities; Similar instructions have been issued by the Central Government on 16th June 2009 advised the State Governments to adopt integrity pact in major procurements;

vi) India is amongst the countries who have signed the United Nations Convention against Corruption;

vii) Introduction of e-Governance and simplification of procedures and systems;

viii) Issue of Citizen Charters.

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति जी, इस सवाल का जवाब पढ़कर मैं थोड़ी हैरत में पड़ गया हूं, क्योंकि अभी जब मैं मंत्री जी का जवाब पढ़ रहा था, तो इसमें मंत्री जी के बारे में जो qualification लिखी है, आधा दर्जन से ज्यादा विभागों के ये मंत्री हैं और इंचार्ज हैं, इसमें यह लिखा हुआ है, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। अब मैं यह नहीं सोच पाता कि जो व्यक्ति आधा दर्जन विभाग देखता है, पृथ्वीराज चौहान जी, जिन्होंने जवाब दिया ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप सवाल पूछ लीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्र : जो मंत्री आधा दर्जन विभाग देखता है, वह कोई भी विभाग समझने लायक रहता है या नहीं यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप सवाल पूछ लीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्री जनेश्वर मिश्र : वैसे भी ऐसे आदमी खुद जवाब तैयार नहीं करते, अफसर लोग जवाब तैयार करते हैं और अफसरों के भ्रष्टाचार के बारे में ही यह सवाल पूछा गया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के बारे में अफसरों पर, अधिकारियों पर जो आरोप लगे हैं कि यह दुनिया में सबसे भ्रष्ट अफसर है, क्या राजनीतिक स्तर पर या जजों के स्तर पर इसकी जांच कराई जाएगी? मंत्री जी, अफसरों को बचा दें और अफसर, इन लोगों को बचा दें, यह तो चलता रहता है, यह मैं जानता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट के स्तर पर या जजों के स्तर पर इस बात की जांच हो, क्योंकि अफसर हमारे हैं और यदि इन पर तोहमत लगती है, तो हम अपने को बदनाम महसूस करते हैं। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस तोहमत को साफ करने के लिए मंत्री महोदय इस तरह की कोई सार्वजनिक जांच कराएंगे?

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Sir, the reply that has been furnished to the hon. Member is based on certain reports that have been published in the Indian media. Sir, one of the reports is a Report by a Consultancy firm which studied twelve countries in South Asia and they had talked about the efficiency of the Government, not about corruption. This Report is made by a Hong Kong-based organisation called 'Political and Economic Risk Consultancy'. This Report has ranked Indian bureaucracy as least efficient, not most corrupt. The second report that has been referred to is the Report of the Transparency International, which is a world-renowned NGO. It publishes Global Corruption Parameters every year. Now, Transparency International's 2009 Report is there. They have found that political parties and civil servants are perceived – it is a perception index – on an average to be one of the corrupt sections around the world. We have these two documents which have been widely reported. But I appreciate the point raised by the hon. Member. The situation is not

very happy. We have several methods in our country to tackle corruption. We have at our disposal the current legislation, the mechanism of the CVC and the CBI and the laws that we have enacted recently like Right to Information Act which seeks to increase the transparency in the Government. We are using e-governance techniques to make it more transparent. We are working on all these fronts. But a lot more needs to be done. I appreciate the concern of the hon. Member and we have noted down the suggestions of the hon. Member.

श्री जनेश्वर मिश्र : सर, अगर हांगकांग की Political and Economic Risk Consultancy and Transparency International ने least competent कहा है, तो इसका मतलब है most corrupt. 'Centre for Management Studies' की रिपोर्ट में भी आप देखेंगे कि भारत की इस अफसरशाही की टीम को बहुत ही भ्रष्ट कहा गया है। वर्ल्ड बैंक ने भी भारत के अफसरों को उसकी स्कीमों को लागू करने के मामले में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। ऐसा नहीं है कि यह बात एक जगह कही गई है।

सर, मैं चाहूंगा कि इस रिपोर्ट के आधार पर मंत्री जी, अब फिर मैं उस बात को दोहराऊंगा कि अफसरों के बारे में सार्वजनिक जांच होनी चाहिए और एक सख्त किस्म का पैरामीटर तय होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो चार साल या पांच साल के लिए temporary मजदूर होते हैं और ये परमानेंट होते हैं। अब अगर परमानेंट भ्रष्ट हो गए तो वे हमको भी भ्रष्ट बना देंगे। फिर हम उनको बचाएंगे और वे हमको बचाएंगे। इस भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए जरूरी है कि संसदीय प्रथा और अफसर शाही, दोनों पवित्र रहें। आप इसे गंगा जल की तरह पवित्र बनाएं, तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन आप इसके लिए एक बार जांच कराइए?

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: The suggestion of the hon. Member is noted down. The Government is very serious about fighting the scourge of corruption. We are strengthening the laws. We have issued a whistle-blower resolution in 2004 which we are trying to convert into a legislation. It is under active consideration of the Government. Every Department has an action plan to fight corruption. I noted down the concern of the hon. Member and the Government is very serious about zero-tolerance to corruption.

श्री बृजभूषण तिवारी : महोदय, अभी मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार को गंभीर माना है, परंतु यह जवाब आधा-अधूरा है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस समय देश के अंदर, यह तो ठीक है कि विदेशी यानी बाहर की एजेंसी ने एक अपना perception दिया है, लोगों में यह विश्वास जम गया है कि हमारी नौकरशाही और विशेषकर उच्चाधिकारी ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं। इस दौर में और भी यह बात प्रबल हुई है, जब से यह नई उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है और यह केवल कोई क्षेत्र, कोई विभाग...

श्री सभापति : आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री बृजभूषण तिवारी : तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जो कानून बने हैं, क्योंकि उनमें कई खामियां हैं, एक खामी तो यह है कि अगर किसी उच्च अधिकारी को ...

श्री सभापति : नहीं, आप सवाल पूछिए। आप कानून पर कमेंटरी कम कीजिए।

श्री बृजभूषण तिवारी : मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का जो प्रोविज़न है, जिसमें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है ...(**व्यवधान**)...

श्री विनय कटियार : सर, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री जनेश्वर मिश्र : यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री सभापति : चर्चा का प्रस्ताव आप ही लोग देते हैं। ...(**व्यवधान**)... देखिए, टाइम खत्म हो रहा है।

श्री बृजभूषण तिवारी : भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकद्मा चलाने के पूर्व जो अनुमति लेनी पड़ती है, क्या सरकार इस नियम को बदलने का विचार कर रही है?

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Sir, this provision for seeking prior permission of the appropriate authority has been there in the law for a long time only to avoid frivolous harassment and prosecution of public servants who are trying to do that job. Many times, I have found out that there are corporate rivalries and all that, which creates many RTI enquiries also. So, Sir, this protection has been given to the public servants and Government servants, क्योंकि हम सब भी public servants हैं, इस कानून के अंदर हम सब भी public servants माने गए हैं, तो इनका protection करने के लिए appropriate authority की permission का प्रावधान है, जो हम सही मानते हैं।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि यह Hong Kong based Political and Economic Risk Consultancy और Transparency International - जो दो संस्थाएं हैं, इनकी world में क्या credibility है? क्या इन्होंने जब भारत में सर्वे किया, तो भारत की कोई संस्था इनके साथ युक्त थी? उन्होंने शायद उनके कोऑपरेशन में कोई डाटा कलेक्ट किया है या वेबसाइट देखकर और अखबारों में पढ़ी-पढ़ाई खबरों को देखकर इन्होंने यह रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब भारत destination for Investment बनता है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय षडयंत्र भी चलता है। अभी-अभी एक रिपोर्ट आई है, वह है World Bank की रिपोर्ट "Doing Business in India, 2009"– वह वहां पर राज्यों को अच्छे रैंक दे रही है, दुनिया के किसी भी कंट्री के साथ comparatively और दूसरी तरफ यह जो Hong Kong की रिपोर्ट है, उसको contradict करती है। तो इन दोनों का आपने comparison करके कोई विचार किया है? सच्चाई क्या है और तथ्य को जानने के लिए, या आपके विभाग में आपने कुछ किया है कि सी.बी.आई. ने इतने केस फाइल किए? ज्यूडीशियरी के खिलाफ तक केस फाइल हुए और अफसरों के खिलाफ केस फाइल हुए। फाइल होते वक्त तो बड़े-बड़े ...

श्री सभापति : टाइम खत्म हो रहा है अहलुवालिया जी।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : किंतु सज़ा के टाइम में acquit हो जाते हैं, इसके बारे में आपने कोई आकलन किया है?

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Sir, the hon. Member has asked two important questions. As he has said himself, the first survey is by a private risk assessment agency, called, the Political and Economic Risk Consultancy. It is a private agency which has rated twelve countries of South Asia and it has termed them as 'most efficient', or 'least efficient'. The word 'corruption' has not been used by this agency. While the Transparency International, every year, produces a perception index of corruption. In that, 2001's report, it had covered 133 countries. Now, it has gone to 180 countries. And, in that survey, India's rank was 71st out of 90 countries, and in 2008, it is 85th out of 180 countries. The index has gone up which means more transparency and less corruption. From 2.7 in 2001, it has gone up to 3.4 in 2008. We are not very happy with this number also, but the impression

also is that the Government's steps have been effective. That has been reported in the Transparency International's survey.

As far as the CBI is concerned, the second part, its conviction rate has been 66 per cent. We are trying to improve it still further. All-India figure is about 40 per cent. But, the CBI's conviction rate of cases, which it is investigation and prosecuting, is about 66 per cent.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

———————

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Racial discrimination in French airlines

†*86. SHRI MOTILAL VORA:
SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI:
Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn towards the incident which occurred in May, 2009 of racial discrimination by the French Airlines involving Indian passengers travelling from Paris to Mumbai;

(b) if so, has the Government not delayed in taking prompt action keeping in view the gravity of this incident; and

(c) the progress made in the dialogue with the French Government to ensure that such racial discrimination by French Airlines may not happen with Indians in future?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S.M. KRISHNA): (a) Government is aware of two incidents of alleged discrimination by Air France involving Indian passengers travelling from Paris to Mumbai on 10 and 24 May, 2009 who were in transit without valid visas at the Charles de'Gaulle Airport in Paris. Both incidents took place during unscheduled halts in Paris. While some passengers of other nationalities were given transit visas, provided accommodation and taken care of, the Indian passengers complained that they were kept at the airport for a long period.

(b) and (c) Government acted with utmost urgency in the matter taking the following actions:

(i) Our Ambassador in Paris took up the matter with the Vice President in the office of Chairman, Air France, immediately after the incident on 11 May 2009, who clarified that the delay in transferring passengers to hotels was caused mainly due to immigration officials. Subsequently, Air France also issued a public apology. General Manager of Air France to India was summoned by the Ministry of Civil Aviation on 15 May 2009. He also profusely apologised on behalf of the airline for the treatment meted out to Indian passengers.

(ii) Our Ambassador in Paris wrote to the Minister of Immigration, Government of France *vide* letter dated 13 May 2009 seeking a review of the procedures laid down for transit visas for Indian nationals so that legitimate travellers from India are not seriously inconvenienced. A Note verbale seeking similar review of procedures for issue of transit visas was also sent to the French Ministry of Foreign Affairs on 14 May 2009.

† Original notice of the question was received in Hindi.